अमृत वाणी

लोगों को सच्चा स्वराज या लोकतंत्र कभी भी असत्य और अहिंसा के बल से प्राप्त नहीं हो सकता है।

–लाल बहादुर शास्त्री,

एक और ट्रेन हादसा

पश्चिम बंगाल के मालदा से दिल्ली जा रही न्यू फरक्का एक्सप्रेस उत्तरप्रदेश में लखनऊ से 65 किलो मीटर दूर रायबरेली जिले के हरचंदपुर स्टेशन के आऊटर में 10 अक्टूबर के तड़के दुर्घटनाग्रसत हो गई जिससे ट्रेन में सवार सात लोगों की मौत हो गई तथा लगभग तीन दर्जन लोग घायल हो गए।

हादसे में ट्रेन का इंजिन और उससे लगे सात डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतर गए जिनमें एक सामान्य और छह स्लीपर कोच शामिल थे। जाहिर तौर पर ये बोगियां यात्रियों से भरी थी। प्रातः लगभग 6.50 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब लोग सुकून से निद्रालीन थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी यह सुकून की नींद चिरनिद्रा में बदल जायगी।

फिर भी अगर यह दुर्घटना किसी तकनीकी अथवा आकस्मिक कारण से हुई होती तो शायद लोग अपनी किस्मत को दोष देकर किसी तरह दिल को तसल्ली दे सकते थे मगर बदकिस्मती यह है कि हर बार की तरह इस बार भी मानवीय भूल और लापरवाही की यह दर्दनाक कीमत मासूम यात्रियों को चुकानी पड़ी।

जैसा कि दुर्घटना के कारणों के बारे में प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा रहा है जिस पटरी पर यह ट्रेन तेज गति से दौड़ रही थी, कुछ दिन पहले ही उसकी मरम्मत की गई थी, इसलिए इस आशंका को नजरदांज नहीं किया जा सकता कि मरम्मत के कार्य में चूक अथवा लापरवाही के कारण ही ट्रेन बेपटरी हुई होगी।

केवल यही नहीं, इस मामले में स्टेशन मास्टर की लापरवाही और भी गंभीर है। उनके द्वारा गलत सिगनल देकर ट्रेन को गलत पटरी पर भेजा जाना इस दुर्घटना के पीछे एक बड़ी मानवीय भूल ही नहीं बल्कि गुनाह समझा जाना चाहिए।

ट्रेन का सही और सुरक्षित संचालन पूरी तरह से रेल कर्मचारियों पर निर्भर होता है। अगर वे ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो इस तरह के हादसे और यात्रियों की जान दांव पर लगना अवश्यमभावी है। उसी तरह रेल से संबंधित मरम्मत हो या फिर कोई भी अन्य कार्य सबकी जिम्मेदारी उन्ही की है। उसके बावजूद वे इसमें किसी भी तरह की ढिलाई, लापरवाही अथवा तुष्टिकरण की गुंजाइश कैसे छोड़ सकते हैं जबकि उन्हें यह भलीभांति ज्ञात है कि उनके कर्तव्य निर्वहन में जरा सी चूक सैकड़ों यात्रियों के जान पर बन आ सकती है।

आश्चर्य की बात यह भी है कि स्टेशन के आउटर के करीब यह हादसा हुआ फिर भी रेल्वे की ओर से यात्रियों तक मदद पहुंचने में एक घंटे का समय लग गया। यह तो आसपास रहने वाले ग्रामीणों का बढ़प्पन है कि सूचना मिलते ही वे यात्रियों के सहायतार्थ दौड़ पड़े और उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया। चूंकि डिब्बों में फंसे यात्रियों को गैस कटर के सहारे बोगियों को काटकर निकालना पड़ा इसलिए तकनीकी सहयोग की जरूरत अधिक थी लेकिन अगर मानवीयता की भावना प्रबल हो तभी ऐसी सहायता कुछ त्वरित रूप से पहुंचाई जा सकती है। बहरहाल दुर्घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट अभी आना शेष है। वहीं घायलों को श्रेष्ठतम उपचार मिले यह सुनिश्चित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्घटना के जिम्मेदारों को तो ऐसी सख्त सजा मिलनी ही चाहिए जो दूसरों के लिए सबक बन सके।

राज काज

दूल्हे को गिफ्ट में मिला पेट्रोल

देश में पेट्रोल.डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जहां विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इसके ही चर्चे हो रहे हैं। सभी मूल्यवृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफआवाज बुलंद कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में जो हुआ उसका जिक्र अब पूरे देश में हो रहा है। दरअसल तमिलनाडु के एक विवाह समारोह में दूल्हे को अजीबों.गरीब उपहार मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दूल्हे को उसके दोस्तों ने पांच लीटर पेट्रोल उपहार स्वरूप दिया, जिसे घरातियों और बरातियों ने ठहाकों के साथ स्वीकार भी कर लिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे लोगों ने शेयर करना शुरु कर दिया है। गौरतलब है कि पेट्रोल 90 रुपए लीटर के करीब पहुंच गया है।

अब आधार हटवाने की लाइन

जिन लोगों ने आधार बनवाने के लिए लाइन लगाई थी और उसके बाद बैंकों और अन्य जगहों में आधार जुड़वाने के लिए लाइन पर लगे थे अब उन्हें इसे हटवाने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके बाद समझा जा रहा है कि लोग अपने बैंक खातों से आधार लिंक को हटवाना चाहेंगे, इसके साथ ही स्कूल और मोबाईल फोन पर से भी आधार लिंक हटवाने के लिए लोगों को अब मशक्कत करनी पड़े तो बड़ी बात नहीं होगी। इसे लेकर विरोधियों को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का अवसर मिल गया है। विरोधी कह रहे हैं कि सरकार ने मनमर्जी से काम किया है, इसलिए आमजन को यह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वर्ना यदि सरकार ने नियमबद्ध फैसले लिए होते और काम भी नीयम से होते तो ये परेशानियां आमजन को नहीं उठाना पड़तीं। कांग्रेस ने तो पहले ही कहा है कि अनुभवहीनता का परिचय मोदी सरकार ने दिया है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है।

देवी कुष्माण्डा इस चराचार जगत की अधिष्ठात्री

नवरात्रि का चौथा दिन

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे। सर्वस्यार्तिहरे देवी कूष्मांडा नमोस्तु ते।। देवी महात्मय के प्रधानिक रहस्य में जिस महालक्ष्मी देवी से आदि देव और महादेवियों का जन्म हुआ उस महाशक्ति भगवती का एकीकृत रूप है नवदुर्गा।

मां दुर्गा के नव रूपों में चौथा रूप है कुष्मांडा देवी का दुर्गा पूजा के चौथे दिन हमें इसी देवी की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है कुत्सितर ऊष्मा कूष्मा.त्रिविधतापयुत.संसार स अण्डे मांसपेश्यामुदररूपायां यस्यार सा कूष्मांडा। इसका अर्थ है वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है वह कूष्माण्डा हैं। देवी कूष्माण्डा इस चराचार जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राय था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंड सैकड़ो सूर्य की प्रभा से प्रदिप्त है उस समय प्रकट हुई उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गयी और जिस प्रकार फूल में अण्ड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान मां की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मण्ड का जन्म हुआ अतर यह देवी कूष्माण्डा के रूप में विख्यात हुई इस देवी का निवास सूर्यमण्डल के मध्य में है और यह सौर मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं।

देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं अतर इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में मशर कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, च तथा गदा है।

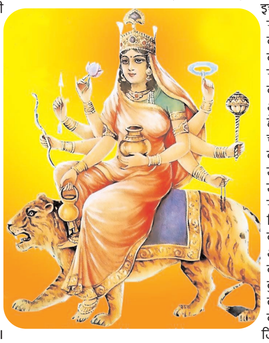

देवी के आठवें हाथ में बिजरौंके कमल फूल का बीजद्ध का माला है है यह माला भक्तों को सभी प्रकार की ऋद्धि सिद्धि देने वाला है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करता है उसके सभी प्रकार के कष्ट रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। जो साधक कुण्डलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी अराधना में समर्पित हैं उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कूष्माण्डा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए फिर मन को अनहत में स्थापित करने हेतु मां का अशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कूष्माण्डा सफलता प्रदान करती हैं जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और मां का अनुग्रह प्राप्त करता है।

दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कूष्माण्डा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चन्द्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफविरजामन हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्माण्डा की पूजा करेर पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र का ध्यान करें सुरासम्पूर्णकलशं रूधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे।। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्रीहरि की पूजा देवी देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए इस अवसर पर देवी को कुम्हर चढ़ाने का विधान है। कुम्हर को देश के अन्य भागों में लोग अलग अलग नाम से जानते हैं कहीं लोग इसे पेठा कहते हैं तो कहीं घीया कहते हैं।

अमित व्यास

(ये लेखक के अपने विचार है)

गठबंधन की लीला से मुक्त मायावती

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के बोल बोलने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य.प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कन्नी काटने का फैसला लेकर गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस को यह निर्णय जहां करारा झटका है, वहीं अंदरूनी तौर से भाजपा की बांछें खिल गई हैं। दरअसल कांग्रेस ने इन तीन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की बुनियाद पर चुनावी वैतरणी पार करने का ताना.बाना लगभग बुन लिया था। लेकिन मायावती ने राजनीति के रण में पहले उन अजीत जोगी से समझौता किया, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ों में मठ्ठा घोल चुके हैं और अब मध्य.प्रदेश व राजस्थान में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की घोषणा करके एक बार फिर कांग्रेस को सकते में डाल दिया है। मायावती की राजनीतिक चालों को चलने वाले जानते हैं कि उनका किसी भी दल से स्थायी गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला। इसीलिए उन्हें ष्माया महा ठगिनी, सब जग जानीष् की संज्ञा दी जाती रही है। अर्थात माया चलायमान हैं। माया की ठौर बदलने की प्रकृति है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह कब किसके अंग लग जाए। बहरहाल इन चुनावों में माया एकला चलो की नीति पर चलती दिखेंगी।

मायावती को समझना दूर की कौड़ी है। इसीलिए उन्होंने अपने फैसले पर कहा है कि ष्कांग्रेस के भीतर एक तरह का जातिवादी और सांप्रदायिक मानस काम करता है, जो भाजपा को लाभ पहुंचाना चाहता है। नतीजतन भाजपा से समझौते में रोड़ा अटका रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि मायावती प्रवर्तन निदेशालय और अनुपात हीन संपत्ति के मामले में सीबीआई के दबाव में हैं। सिंह की बात में दम है, क्योंकि एक तो मायावती की राजनीति का आधार ही केवल जाति है और अब जाति के मामले में भी उनका दायरा सिमट रहा है। वे केवल अनुसूचित जातियों में अपनी ही जाति की धुरी पर पर केंद्रित रह गई हैं। दूसरे, मायावती का माया से मोह किसी से छिपा नहीं है। नोटों की माला पहनते.पहनते वे हाल ही में 50 करोड़ की लागत से निर्मित आलीशान बंगले में रहने लगी हैं। जो विलास और वैभव के भौतिक संसाधनों से समृद्ध है। यही वे उपाय है, जो माया को बेनामी संपत्ति एकत्रित करने से जोड़ते हैं। इस लिहाज से दिग्विजय सिंह का यह कहना कि वे ईडी और सीबीआई के दबाव में हैं तो यह तथ्य बेवजह नहीं है। चुनांचे सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव और उनके दल को अपनी जान का दुश्मन मानने वाली मायावती का चुनावी गठबंधन सपा से हो चुका है घ् संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस का साथ देने वाली बसपा ने बढ़ते डीजल.पेट्रोल के दामों के खिलाफ किए गए भारत बंद में राहुल का साथ देने से इनकार कर दिया था। दरअसल मायावती ही नहीं इस समय सभी दल प्रमुख फूंक.फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मायावती और भी ज्यादा सधे कदमों से इसलिए चल रही हैं, क्योंकि वे अनुभव कर रही हैं कि इन राज्यों में कांग्रेस से को समझौते के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएं मुश्किल हैं ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि वे महज एक ही जाति के वोट बैंक पर धुवीकृत हो गई हैं। मध्य.प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें क्रमशरू 6.29, 3.4 और 4.27 प्रतिशत ही वोट मिल पाए थे। बसपा मप्र में 4, छत्तीसगढ़ में एक और राजस्थान में 3 सीटें ही जीत पाई थी। उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर.प्रदेश से थी, लेकिन वहां उनका मोदी और योगी के नेतृत्व में एक तरह से सूपड़ा साफहो गया। साफहै माया और बसपा उतार पर हैं।

उप्र में मायावती दलित, सवर्ण और पिछड़ों का बेमेल खेल खेलकर सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं। इसीलिए अब वे प्रधानमंत्री बनने की महत्वकांक्षा पाले हुए हैं। लेकिन अब एससी.एसटी एक्ट को लेकर पिछले 4.5 माह में जिस तरह से दलित चेतना और सवर्ण आंदोलन के सिलसिले ने राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसके चलते इन तीन राज्यों में कांग्रेस हो या भाजपा चुनाव कांटे की टक्कर में बदल गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मायावती का कांग्रेस के बागी जोगी से हाथ मिलाना और मध्य.प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से गठबंधन न हो पाना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि कांग्रस और बसपा के बीच समझौता हो जाता तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी आसान हो जाती। हालांकि कांग्रेस राजस्थान में माया से गठबंधन नहीं होने के बावजूद मजबूत है। कांग्रेस माया से तालमेल नहीं होने का कारण सीटों का बंटवारा रहा है। दरअसल कांग्रेस का विभिन्न गढ़ों में जाति आधारित जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, वह अपने प्रभुत्व को गठबंधन के नाम पर बलिदान करने के पक्ष में नहीं है। इस दबाव के चलते कांग्रेस, बसपा को राजस्थान में 10, मप्र में 20 और छत्तीसगढ़ में मात्र 6 सीटें देने को तैयार थी, जबकि मायावती इनसे दूनी सीटें चाहती थीं। समझौते की बातचीत के दौरान अपनी बात रखते हुए मायावती ने दलील दी थी कि ष्मेरा मतदाता एक वोट बैंक की तरह गठबंधन वाले दल को शत.प्रतिशत स्थानांतरित हो जाता है, जबकि सवर्ण मतदाता ऐसा नहीं करता।ष् लेकिन गंगा में अब बहुत पानी बह चुका है। मायावती का जनाधार खिसका है। उसका झुकाव अब फिर से कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि बसपा की इन तीनों राज्यों में अकेले दल के रूप में सत्ता पर काबिज होने की संभावना दूर.दूर तक नहीं है। गोया, मायावती को अब उनका कोई पुख्ता वोट.बैंक है, इस मुगालते से बाहर आना चाहिए। इस तथ्य का सत्यापन चुनावी आंकड़ों से होता है। अविभाजित मप्र में 1998 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 6ण्1 प्रतिशत वोट हासिल करके 11 सीटें जीती थीं, किंतु 2013 में वह केवल 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, किंतु 2013 में वह केवल 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। बसपा का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्वालियर.चंबल अंचल में है। इस क्षेत्र की 34 सीटों पर उसे 1998 में 20ण्3 प्रतिशत वोट मिले थे, किंतु 2003 में यह प्रतिशत घटकर 15, 2008 में 20 और 2013 में 16 रह गया।

इस बार इन तीनों राज्यों में से सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव मप्र में देखने को आएगा। भाजपा मोदी मैजिक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों के बूते जीत की उम्मीद लगाए हुए है। अलबत्ता अनुसूचित जाति.जनजाति कानून में संशोधन करने की भूल उसकी जीत में बड़ी बाधा बनकर पेश आ रही है। सपाक्स ने राज्य की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके उसे खुली चुनौती दे दी है। करणी सेना भी काले झण्डे हाथ में लिए भाजपा के विरोध में खड़ी है। इधर कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिशों में लगे हैं। कमलनाथ को अपने बढ़े कद के चलते हर बात के अनुमोदन के लिए दिल्ली ताकना नहीं पड़ता है। इसीलिए सिंधिया और सिंह कमलनाथ के साथ बिना किसी हिचक के है। किस नेता को कितना वजन और काम देना है, इसका निर्णय वे स्वयं लेने का हक रखते हैं। इसीलिए कांग्रेस की चुनावी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन सधी हुई है। लिहाजा यह कतई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का बसपा से गठबंधन नहीं हुआ तो मध्य.प्रदेश में उसकी ताकत कम आंकी जाए।

प्रमोद भार्गव

(ये लेखक के अपने विचार है)

क्या हरियाणा आप को तलाश है कद्दावर नेता की

ज्यों ज्यो वर्ष 2019 नजदीक आता जा रहा है , त्यों त्यों हरियाणा की राजनैतिक पार्टियों की डफलियां तेज होती जा रही हैं। भले ही डफली बजाने वाले अलग अलग हों , भले ही आवाज कम ज्यादा हो , परन्तु राग सभी एक ही अलाप रहे हैं दकुर्सी राग। वर्ष 2014 में कांग्रेस के शासन से आजीज आ चुके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पटल पर नये उभरे नेता नरेंद्र मोदी की बातों और लोभ भरे आश्वासनों पर इतना भरोसा कर लिया कि केंद्र तथा हरियाणा प्रदेश दोनों जगह भाजपा को सत्तासीन कर दिया। पांच साल पूरे होते होते मतदाताओं का तो पता नहीं मोह. बिछोह हुआ है या नहीं हुआ है , परन्तु आज हरियाणा में राजनेताओं की यह स्थिति हो गयी है कि उन्हें सत्ता का ताज रात को स्वप्न में भी अपने ही सिर पर सजता दिखाई देने लगा है। खुद भाजपा में वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह कई कद्दावर तो क्या बौने बौने नेता लोग भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने कब्जे में करने को आतुर लग रहे हैं। भाजपा की इसी 2019 में आयोजित होने वाली कुर्सी रेस में कई घोड़े अपनी लगाम को त्याग बेलगाम हो रहे हैं। और समय समय पर खट्टर के चाबुक की परवाह किये बिना पार्टी लाइन से हटकर ब्यान बाजी करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपनी सुपरेमेसी सिद्ध करने को तैयार रहते हैं। मोदी को हरियाणा में बुलाने के लिए भी अलग अलग तिथियों के कार्यक्रमों को अपने अपने हिसाब से तय कर अपना आधिपत्य दिखाना चाहते हैं।

भाजपा की इसी खींचतान व घटती दिखाई दे रही साख को भांपकर हरियाणा में अन्य प्रभावशाली दल कांग्रेस तथा इनेलो जैसी पार्टियां तो क्या चुनाव के बरसाती माहौल की नमी महसूस कर कुकरमुत्तों की तरह जन्म ले रहे अन्य नये नये दल भी ताजपोशी की कल्पना करने लगे हैं। जहाँ आम आदमी पार्टी जगह जगह ष्हमारा परिवार दृ आम आदमी पार्टी के साथ के पोस्टर चिपका कर लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है , वहीं कांग्रेस को भी गाँव स्तर पर युवाओं की हताशा दिखाई देने लगी है। पांच अक्टूबर को जींद में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को युवाओं की इसी हताशा को पार्टी से जोड़ने का विकल्प नज़र आया। शिपछले चुनाव में भाजपा ने जिस यूथ को टारगेट कर सत्ता हासिल की थी , वह यूथ अब पूरी तरह से उससे खफा है , अब कांग्रेस का आगामी चुनाव में इसी यूथ पर फोकस रहेगा। ष्हर घर तक कांग्रेस अभियान के तहत एक बूथ पर दस सहयोगी बनाए जायेंगे। परन्तु किसी के पास आसमां नहीं है तो किसी के पास ज़मीं। दिल्ली में प्रचण्ड बहुमत पाकर गद गद हुई आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है कि यदि हरियाणा में भी खेत जोत किया जाए तो बम्पर फसल पाई जा सकती है। परन्तु हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास टोरा फेरी करने वाले टोपीधारी सर्वेयर तो दिखाई दे रहे हैं , सूड़ ; झाड़ झंखाड़ द्ध काटने वाले वर्कर तथा खेत जोतने वाला मुख्य ष्हालीष् नदारद लगता है। पार्टी के पास ग्रामीण क्षेत्र की नब्ज पहचानने वाले नेता का अभाव लगता है। देहात में जातीय तथा गौत्रीय कारक वोट बैंक को प्रभावित करते हैं तथा ग्रामीण एवं किसान के मुद्दों की अनदेखी किसी भी पार्टी को गाँव के मतदाता से जुड़ने से रोकती है। केजरीवाल द्वारा पंजाब के चुनाव के समय एस वाई एल पर दिया गया बयान भी किसान के वोट लेने में बाधक रहेगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब चुनाव में केजरीवाल ने एस वाई एल पर हरियाणा के हक़ को सिरे से नकार दिया था।

वर्तमान में पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो वोट खींच सके। हल्का वाइज तो ऐसे नेताओं तथा वर्कर्स का अभाव है ही , प्रदेश स्तर पर भी कोई कद्दावर तथा करिश्माई नेता न होने की वजह से धरातल पर केवल पोस्टरबाजी ही दिखाई दे रही है। वोटर का अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ाव न देख शायद पार्टी के कर्णधारों को भी लगने लगा है कि बिना मजबूत खेवैये के अकेले कुछ सवारियों द्वारा हाथ से पानी पीछे धकेलने से नाव को नहीं खेया जा सकता है।

जग मोहन ठाकन

(ये लेखक के अपने विचार है)

लोकतंत्र में नौकरशाही की सेहत

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में कार्यकाल के अधबीच यह चर्चाएं चौकाने वाली हैं कि केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के बीच गुजराती और गैर गुजराती कैडर के अफसरों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। पिछले तीन चार माह से शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और विश्वसनीयता को लेकर ऐसा माहौल बना है। जिसने केंद्र सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त सचिव के पद पर सीधी भर्ती किए जाने से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पहले ही नाराज थे। लेकिन गुजरात कैडर के अधिकारियों का वर्चस्व पिछले 2 वर्षों में काफी बढ़ जाने से गैर गुजराती अफसर खिन्न हो रहे हैं।

कहा जा रहा है कि पीएमओ से सीधे जुड़े होने के कारण गुजरात कैडर के अधिकारी अन्य कैडर के अधिकारियों को अविश्वसनीय मानते हुए, उनके साथ निम्न दर्जे का व्यवहार करते हैं, जिसके कारण शीर्ष स्तर के अधिकारियों में इस समय टकराव की स्थितियां उभर आयी हैं। गुजरात कैडर और अन्य कैडर के अधिकारी एक दूसरे को निपटाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट,जनहित याचिकाओं, छापेमारी और एक.दूसरे के खिलाफ फाइलों में टिप्पणी करने, मीडिया में खबरें लीक करने,फोन टेप कराने जैसी कार्यवाही इन दिनों अधिकारियों के बीच काफी बढ़ गई है। शीर्ष स्तर के अधिकारी फोन टैपिंग की आशंका के चलते भयभीत हैं और निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने से बचने लगे हैं , जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को पहली बार विषम स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी शीर्ष स्तर के अधिकारियों में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। पीएमओ के पास सारी शक्तियां केंद्रित हो जाने के कारण अब संयुक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं।

हाल ही में गृह मंत्रालय में गृह सचिव रहे राजीव महर्षि को कश्मीर के राज्यपाल बनाने की चर्चाएं थी।किंतु शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच की टकराहट को देखते हुए इस पद पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सतपाल मलिक की नियुक्ति कर दी। जबकि पिछले 40 वर्षों से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर नौकरशाहों की नियुक्ति होती रही है।

यह सुनना दुखद है कि अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान के कारण सत्ता के गलियारे में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे विवादास्पद निर्णयों की डिटेल अधिकारियों द्वारा ही विपक्ष को उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव होने हैं ऐसी स्थिति में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की यह टकराहट सरकार पर भारी पड़ सकती है।

अजित वर्मा

(ये लेखक के अपने विचार है)